due from 1st July, 1991 would be calculated thereafter.

(c) Under the existing orders, the instalment of Dearness Allowance due from 1st July is payable with the salary of September.

स्टेट बैंक आफ इण्डिया इत्यादि द्वारा कमजोर वर्गों को ऋण का वितरण

1304. **श्री राम नरेश यादव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में उन कृषकों, कमजोर वर्गों से संबंधित व्यक्तियों, बेरोजगार छात्रों और निम्न वर्गों के व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिनको 1988 से लेकर आज तक स्टेट बैंक आफ इण्डिया की शाखाओं और इससे सम्बद्ध बैंकों द्वारा ऋण प्रदान किए गए हैं ;

(ख) इस संबंध में प्राप्त किए गए आवेदनों की संख्या कितनी है कितने आवेदन अस्वीकृत कर दिए गए हैं तथा कितने आवेदन विचाराधीन हैं तथा इनका वर्षवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि आवेदन प्राप्त करने के पश्चात ऋण देने में अत्यधिक विलम्ब हुआ है और कुछ दलालों ने आवेदकों से कमीशन भी लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो कर्जदारों को दलालों से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) आंकड़ा सूचना प्रणाली उन किसानों, कमजोर वर्गों के व्यक्तियों, बेरोजगार छात्रों और निम्न वर्ग के व्यक्तियों से संबंधित श्रेणी-वार सूचना नहीं रखती जिन्हें किसी राज्य विशेष में बैंकों की शाखाओं द्वारा ऋण प्रदान किए गए हैं । यह प्रणाली प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या नामंजूर किए गए आवेदन पत्रों की संख्या और विचाराधीन आवेदन पत्रों की संख्या से संबंधित राज्य-वार सूचना भी नहीं रखती है । अलबत्ता, भारतीय स्टेट बैंक और इसके अनुषंगी बैंकों से गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य के कमजोर वर्गों को कुल बकाया राशि की सूचना भेजने के लिए कहा जा रहा है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

(ग) और (घ) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को अग्रिम प्रदान करने के लिए सभी बैंकों को जारी भारतीय रिजर्व बैंक के मार्ग निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि 25,000 रुपए तक की ऋण सीमा वाले सभी ऋण आवेदन पत्रों को दो सप्ताह के अन्दर-अन्दर और 25,000 रुपए से अधिक के आवेदन पत्रों को 8 से 9 सप्ताह के अन्दर-अन्दर निपटाया जाना चाहिए । बैंक शाखाओं को ऋण आवेदन पत्र या तो सीधे ही आवेदकों से प्राप्त होते हैं या राज्य के प्रायोजक एजेंसियों के माध्यम से प्राप्त होते हैं और तदनुसार उन्हें मंजूर किया जाता है । ऋणों के संवितरण में देरी या किसी बिचौलिए द्वारा ऋण-कर्ताओं को परेशान किए जाने से संबंधित बैंकों में प्राप्त शिकायतों को उपचारात्मक कार्रवाई करने के उद्देश्य से बैंकों द्वारा जांच की जाती है ।

Posts of P.G.T. in Central School, Moscow

1305. SHRI ISH DUTT YADAV: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Kendriya Vidyalaya, Moscow had been started in 1987 and posts of PGTs in Science and humanities had been sanctioned therefor;

(b) if so, whether it is also a fact that the post of PGT (History) has remained unfilled for the last four years and if so; and

(c) what steps have been taken or are contemplated to fill the vacancy?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The posting of teachers in Moscow is subject to the Indian Embassy agreeing to provide residential accommodation to the teacher concerned and such accommodation was not available for the teacher selected as Post Graduate Teacher (History). Subsequently in December, 1989 the Indian Embassy intimated that they did not need a Post Graduate Teacher (History) as the Vidyalaya had only one student in the Humanities group at —2 stage and the services of an honorary teacher were available.

Streamlining of growth of Central Schools

1308. SHRI SANTOSH KUMAR SAHU: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government are considering any proposal to streamline the growth of Kendriya Vidyalayas in the present decade ending by 2000 A.D.; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OP HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): (a) and (b) Kendriya Vidyalayas in recent years have been expanding by about 20 Vidyalayas per year, on an average. Future expansion till 2000 A.D. will depend on the availability of funds, the sponsorship of suitable proposals by the user agencies and administrative considerations.

Agreement made between CRPF and Kendriya Vidyalaya Sangathan

1307. SHRIMATI KAILASHPATI: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in March, 1985 an agreement was made between Group Centre CRI'F, Rampur and Kendriya Vidyalaya Sangathan through Vidyalaya Management Committee that 6 additional quarters will 'be provided for post graduate teachers if the Vidyalaya was raised that year to plus two stage with science and humanities streams; and

(b) if so, reasons for non-implementation of the agreement?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SIIRI ARJUN SINGH): (a) and (b) The information is being collected.

Section strength in Central Schools

1308. SHRIMATI KAILASHPATI: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what is the maximum number of students prescribed for a section of a class in a Kendriya Vidyalaya;

(b) whether it is a fact that the section strength in Kendriya Vidyalayas in Metropolitan cities in general and those of Delhi in particular has gone between 50 and 80; and

(c) if so, what are tha reasons for not opening additional sections or for not introducing second shift in such Vidyalayas?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): (a) The maximum prescribed number of students in a section of a class *of* a Kendriya Vidyalaya is 35, except for the North-Eastern Region where the maximum prescribed number is 40.

(b) Yes, Sir, it is a fact that the section strength in some of the Kendriya Vidyalayas in Metropolitan Cities including Delhi has gone up to 50 or more.

(c) This is due to non-availability of infrastructural facilities and of